Workers participation in the management Scheme

2436. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Congress(I) had pledged in its election Manifesto to implement Workers Participation in the Management Scheme; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) The manifesto of the Indian National Congress (I) for the General Elections of 1991 states that it is committed to increasing the workers' participation in management.

(b) A scheme on employees' participation in management was notified by the Central Government on December 30, 1983. It is applicable to all Central Public Sector Undertakings except those which are specifically exempted. A majoriy of the Central Public Sector Undertakings have introduced workers' participation in management at the shop floor and the enterprise level.

The Participation of Workers in Management Bill, 1990 was introduced in the Rajya Sabha on 30th May, 1990. The Bill has not yet been taken up for consideration by the House.

ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर

2437. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 के "फाईनेन्शियल एक्सप्रेस" में रूपीज 14,333 करोर्स प्लान टु क्रियेट 24.5 लैक जॉब्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदाद करने हेतु कोई योजना क्रियान्वित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार पहले से ही एक योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसे "शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना" के रूप में जाना जाता है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अधीन, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान 12.5 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। उपर्युक्त के अलावा, सरकार देश में लघु उद्योगों को भी